(b) and (c) Food grains (wheat and rice) are allotted to the States/Union Territories including Bihar and Uttar Pradesh on a month to month basis having regard to stocks available, seasonal availability, relative needs of various states/ Union Territories and offtake trends. The allotment from Central Pool is supplemental in nature and is not meant for meeting the entire requirement of States and Union Territories. The lifting of foodgrains allotted to Bihar and Uttar Pradesh as generafly been less than the allocation. Once the monthly allocation of foodgrains is made to the States/Union Territories including Bihar and Uttar Pradesh, it is the responsibility of the State Govern-ments to have it lifted and distribute the same to the udsan as well as rural areas on the basis of the need felt by them.

Under the present policy of partial control, the monthly allocation of levy sugar to most of the States/Union Territories are being made on uniform norms of ensuring 425 gms. per capita monthly availability to the projected population as on 1-10-86 effective from 1-2-1987. In addition the Government alIots about one lakh tonnes of levy sugar per annum as festival quota for the country as a whole. The release of free sale sugar for internal con-siunption is regulated by way of monthly release mechanism taking into account the production, stocks, availability of other sweetening agents like gar and khandsari, price trends etc. With a view to augment supply of free sale sugar in the open market and to maintain price of sugar at a reasonable level, the Government has permitted import of sugar under OGL.

Safety of Foodgrain in the godowns

5076. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foodgrains on a very large scale/quantity are lying uncovered/unsafe in various godowns in the country;

(b) if so, what are the delays thereof, 'grain-wise and godown-wisc stating the quantity of foodgrains which became rotten durnig 1991-92 and 1992-93 and losses due to this ;

(c) whether Governnlent is considering to build more godowns to keep the foodgrains fully covered/safe and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what stsps have been taken to keep the total food stock of rice, wheat etc. under full and proper safety in the country ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) No, Sir.

(b) The foodigrains are generally stored in covered godowns. IF COVERED godown space is not available, foodgrains are stored in open under Cover "And plinth (CAP) duly protected with polythene covers. As on 1-3-1994 about 17.38 lakh tonnes of foodgrains were stored in CAP out of the total stocks of 190.24 lakh tonnes of foodgrains held by FCI- The figures relating to the quantity of fodgrains held by FCI. The figures relating. to the quantity of foodgrains became rotten during 1991-92 and 1992-93 and losses on account thereof are not readily available. The information in this regard is being collected from the field offices of the Corporation.

(c) Yes, Sir

(d) During the 8th Five Year Plan there is a proposal to ocnstruct 6.62 lakh tonnes of additional storage capacity to keep the foodgrahi stocks under full and proper safety. Out of the 6.62 lakh ton nes storage capacity, Food Corporation of India has already constructed a capacity of 2.68 lakh tonnes upto 31-3-1994.

चीनी के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य

5077. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में चीनी के उत्पादन हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं;

(ग) चीनी उद्योग में इसके कम उत्पादन के क्या-क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने नागरिक आपूर्ति प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों, सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार के लिए, पृथक पृथक रूप से प्रति किलोग्राम चीनी के क्या-क्या मूल्य निर्धारित किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) चीनी उत्पादन का राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति ने 1992-93 मौसम के लिए 121.68 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 1993-94 चीनी मौसम के लिए 127.76 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था। 1992-93 चीनी मौसम के दौरान चीनी का कुल उत्पादन 106.09 लाख टन हुआ था। चीनी उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि चालू 1993-94 चीनी मौसम में पूरे मौसम के दौरान चीनी का वास्तविक उत्पादन 1992-93 मौसम के उत्पादन से कम होगा।

(ग) चीनी उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से गुड़ व खांडसारी क्षेत्रों की ओर गन्ने के अत्यधिक विपथन के कारण आई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने 1-2-1994 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई की जाने वाली लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। सरकार सुपर बाजार या केन्द्रीय भंडार के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी का मूल्य निर्धारित नहीं करती है।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न से लदे ट्रकों का लापता होना

5078. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या खाद्य मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गेहूं तथा चावल से लदे कई ट्रकों के लापता होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम की ओर से हुई लापरवाही की जांच करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) वह कौन-कौन से मार्ग हैं जहां से ये लापता ट्रक गायब हो गए थे तथा इन ट्रकों में लदे खाद्यान्नों की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की इसमें अंतर्ग्रस्तता होने का कोई संकेत है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) दिसम्बर, 1993 तक पुनर्मिलान न हुए बताए गए 895 ट्रकों (न कि लापता) में से 527 ट्रकों का पुनर्मिलान कर लिया गया है जिससे 368 ट्रक शेष रह जाते हैं। पुनर्मिलान करना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

पंजाब से जम्मू अधिकांशत: रेल द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई की जाती है। जम्मू से श्रीनगर/घाटी में ट्रकों से खाद्यान्न ले जाया जाता है। जो ट्रक श्रीनगर/घाटी में खाद्यान्न लेकर जाते हैं वे वापसी में फल और सब्जियां आदि लाते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जम्मू में स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में पावतियां जमा करवाएं। तथापि, ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां वापस आने पर उन्होंने जम्मू में स्थित कार्यालय में पाव-